+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

YOJANA MAGAZINE ANALYSIS

(योजना पत्रिका विश्लेषण)

(केंद्रीय बजट 2024-25)

(September 2024)

(Part II)

TOPICS TO BE COVERED

- समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय
- भारत की रोजगार गाथा में एक नया अध्याय
- विनिर्माण और रोजगार सृजन: उद्योग का परिदृश्य

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय:

परिचय:

- आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में विकसित भारत और बजट 2024-25 की प्राथमिकता 3 को जोड़ते हुए गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इसमें आर्थिक वृद्धि को समर्थन देने के लिए मजबूत सामाजिक बुनियादी अवसंरचना की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
- आर्थिक सर्वेक्षण में यह अनुमान लगाया गया है कि औपचारीकरण और कौशल विकास के बढ़ने के साथ भारत का रोजगार परिदृश्य बदल रहा है। उदाहरण के लिए, वित्त वर्ष 2014-15 और वित्त वर्ष 2023-24 के बीच EPFO की सदस्यता में 8.4 प्रतिशत की प्रभावशाली CAGR वृद्धि हुई, जो औपचारिक रोजगार में वृद्धि को दर्शाती है। इसके अलावा, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना जैसी पहलों से विनिर्माण क्षेत्र में लाखों नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है जिससे रोजगार को और बढ़ावा मिलेगा।

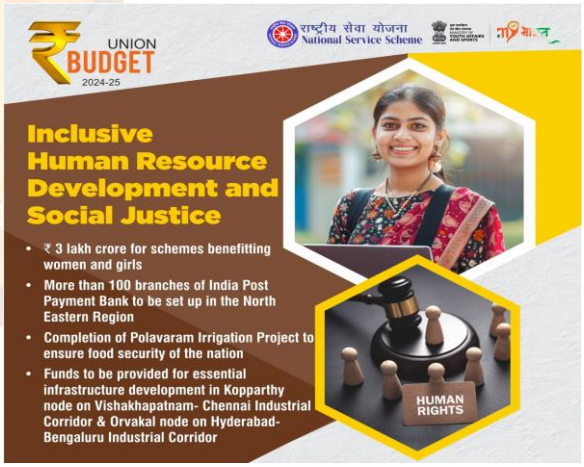

- आर्थिक सर्वेक्षण में यह भी अनुमान लगाया गया है कि भारत की GDP सालाना 7 प्रतिशत या उससे अधिक की दर से बढ़ सकती है बशर्ते कि संरचनात्मक सुधार जारी रहे। इस वृद्धि से लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने और पूरे देश में जीवन स्तर में सुधार की उम्मीद है। हालांकि, इस हासिल करने के लिए समावेशी नीतियों और सामाजिक न्याय के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता की आवश्यकता है।
- वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत भारत का 2024-25 का केंद्रीय बजट 'विकसित भारत' के लिए एक व्यापक विजन प्रस्तुत करता है। इस विजन के केंद्र में बजट की तीसरी प्राथमिकता- समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय निहित है।

समावेशी मानव संसाधन विकास:

- समावेशी मानव संसाधन विकास का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को आर्थिक विकास में योगदान देने और उससे लाभ लेने के लिए आवश्यक कौशल और अवसर प्रदान करना है।
- वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास पहलों के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का पर्याप्त आवंटन किया गया है।

बजट में शिक्षा और कौशल विकास पहलें:

- **1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान:** बजट में सबसे परिवर्तनकारी घोषणाओं में से एक घोषणा 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को हब-एंड-स्पोक व्यवस्था में अपग्रेड करने के लिए पांच वर्षों में 60,000 करोड़ का प्रावधान किए जाने से संबंधित है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि 20 लाख युवाओं को प्रासंगिक और रोजगार योग्य कौशलों का विकास हो। यह पहल भारत के कार्यबल में कौशल अंतर का समाधान करेगी।
- **कौशल ऋण योजना:** बजट में एक संशोधित मॉडल कौशल ऋण योजना भी प्रस्तुत की गई है जिसके अंतर्गत सरकारी गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य वार्षिक रूप से 25,000 छात्रों को सहायता प्रदान करना है ताकि वे बिना किसी वित्तीय बोझ के व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें।
- इसके अलावा, 3 प्रतिशत के वार्षिक व्याज अनुदान के साथ 10 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण प्रदान किया जाएगा जिससे प्रति वर्ष 1 लाख छात्रों को लाभ होगा।

रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं:

- बजट में पांच वर्षों के लिए 2 लाख करोड़ के केंद्रीय परिव्यय के साथ तीन रोजगार से जुड़ी तीन प्रोत्साहन योजनाओं की रूपरेखा दी गई है। ये योजनाएं रोजगार सृजन के विभिन्न पहलुओं को लक्षित करती हैं।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- **योजना-कः** यह योजना पहली वार नियुक्त किए गए कर्मचारियों को 15,000 तक को एक महीने की वेतन सब्सिडी प्रदान करती है। इससे 2.1 करोड़ युवाओं तक इसका लाभ पहुंचने की उम्मीद है, इस पहल का उद्देश्य औपचारिक क्षेत्र में नए श्रमिकों के प्रवेश को आसान बनाना है, जो शिक्षा और रोज़गार के बीच एक महत्वपूर्ण पुल का काम करते हैं।
- **योजना-खः विनिर्माण में रोजगार सृजनः** यह योजना नियोक्ताओं को उनके ईपीएफओ अंशदान के एक हिस्से को कवर करके विनिर्माण क्षेत्र में नए कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसका लक्ष्य 30 लाख युवाओं को रोजगार देना है। विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करके, सरकार एक ऐसे क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है जिसमें बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की क्षमता है।
- **योजना-गः नियोक्ताओं को सहायता:** यह योजना 1 लाख प्रतिमाह से कम आय वाले नए कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ अंशदान के 3,000 प्रति माह तक की प्रतिपूर्ति करती है। इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में 50 लाख नए रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित करना, व्यापक रोजगार वृद्धि का समर्थन करना और नियोक्ताओं के लिए अपने कार्यबल का विस्तार करने में बाधाओं को कम करना है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

सामाजिक न्याय:

- सामाजिक न्याय मानव संसाधन विकास का एक अभिन्न अंग है। सामाजिक न्याय पर बजट का फोकस यह सुनिश्चित करने पर है कि आर्थिक विकास से समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से उपेक्षित और वंचितों को लाभ मिले।

'सैचुरेशन अप्रोच':

- बजट में 'सैचुरेशन अप्रोच' अपनाया गया है जिसका उद्देश्य विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत सभी पात्र व्यक्तियों को शामिल करना है। सैचुरेशन अप्रोच का उद्देश्य एक अधिक समतापूर्ण समाज बनाना है जहां विकास के लाभों को व्यापक रूप से साझा किया जाता है।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो 80 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करती है, इस अप्रोच का यह एक प्रमुख उदाहरण है। इसे और पांच वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है।

महिलाओं के नेतृत्व में विकास:

- महिला सशक्तिकरण सामाजिक न्याय की आधारशिला है। बजट में महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक

का आवंटन किया गया है। यह पर्याप्त निवेश आर्थिक विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति सरकार को मान्यता को उजागर करता है।

- कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास क्रेच और महिलाओं के लिए विशेष कौशल कार्यक्रम जैसी पहलों का उद्देश्य कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है।

आदिवासी कल्याण:

- प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का उद्देश्य आदिवासी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है। इस पहल ने 63,000 गांवों को कवर करने और पांच करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए आवंटन के साथ व्यापक विकास सुनिश्चित करने के लिए एक 'सैचुरेशन अप्रोच' अपनाया है।
- यह कार्यक्रम शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी अवसंरचना और आर्थिक अवसरों पर फोकस करता है जो आदिवासी आबादी के सामने आने वाली अलग प्रकार की चुनौतियों का समाधान करता है।

संभावित प्रभाव:

- बजट के प्राथमिकता 3 के तहत प्रस्तावित उपायों में भारत में महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाने की क्षमता है। शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार में निवेश करके, सरकार का लक्ष्य अधिक सक्षम और प्रतिस्पर्धी कार्यबल

तैयार करना है। इससे उत्पादकता बढ़ेगी, नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और निवेश आकर्षित होगा जिससे सतत आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा।

- सामाजिक न्याय पर ध्यान केंद्रित करने से यह सुनिश्चित होता है कि विकास के लाभ समान रूप से वितरित हों। महिलाओं, आदिवासी समुदायों और पूर्वी राज्यों को लक्षित करने वाली पहलें ऐतिहासिक असमानताओं और क्षेत्रीय विषमताओं का समाधान करती है।

चुनौतियां और विचार-विमर्श:

- हालांकि बजट के प्रस्ताव महत्वाकांक्षी और नेक इरादे वाले हैं, लेकिन उनके सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मजबूत शासन और प्रभावी समन्वय की आवश्यकता होगी।
- यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आवंटित धन का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाए और इच्छित लाभार्थियों तक पहुंचाया जाए। लीकेज और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए।
- इसके अतिरिक्त, कौशल और रोज़गार पहल की सफलता निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है। पाठ्यक्रम तैयार करने, इंटर्नशिप प्रदान करने और रोज़गार के अवसर सृजित करने में उद्योग का सहयोग आवश्यक है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

भारत की रोजगार गाथा में एक नया अध्याय:

रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन के माध्यम से रोजगार के अवसरों में वृद्धि:

- वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में रोजगार कौशल MSME और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सरकार की प्राथमिकताओं को निर्धारित किया।

- उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा 5 योजनाओं और पहलों के पैकेज की घोषणा की, जिसके तहत 5 साल की अवधि में 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के बल पर 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार, कौशल और अन्य अवसर प्रदान किए जाएंगे।
- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को देश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन (ELY) के माध्यम से माहौल बनाने का काम सौंपा गया है। रोजगार सृजन और युवाओं को रोजगार देने पर केंद्रित कई अभिनव योजनाएं शुरू की गई हैं।

फर्स्ट टाइमरः कार्यबल में प्रवेश करने वाले युवाओं के लिए एक जीवन रेखा

- भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को पूरी तरह से तभी साकार किया जा सकता है, जब हमारे युवाओं को सफलतापूर्वक कार्यबल से जोड़ दिया जाता है।

- चाहे वह प्रासंगिक कौशल की कमी हो, कार्य का अपर्याप्त अनुभव हो या प्रतिस्पर्धी बाजार में रोजगार पाने की चुनौती हो, युवाओं के लिए शिक्षा से रोजगार में परिणत होने की प्रक्रिया कठिनाई हो सकती है।
- फर्स्ट टाइमर स्कीम इन चुनौतियों का सीधा जवाब है। औपचारिक क्षेत्र में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को एक महीने का वेतन देकर, सरकार शुरुआत में युवा श्रमिकों की मदद के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।
- यह सहायता प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से वितरित की जाएगी। इसके तहत, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के साथ पंजीकृत फर्स्ट टाइमर कर्मचारियों को तीन किस्तों में 15,000 रुपये तक प्रदान किए जाएंगे।
- 1 लाख रुपये प्रतिमाह वेतन की पात्रता सीमा के साथ, इस योजना से देश भर में 2.1 करोड़ युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।

महत्व:

- इस पहल के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। नए रोजगार की शुरुआत के वित्तीय बोझ को कम करके, फर्स्ट टाइमर स्कीम युवा श्रमिकों की यात्रा को गति देने में मदद करती है। इसके अलावा, युवाओं को औपचारिक कार्यबल में

प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करके, यह योजना भारत के श्रम बाजार को औपचारिक बनाने के व्यापक लक्ष्य में भी योगदान देती है।

विनिर्माण क्षेत्र में रोज़गार सृजनः एक महत्वपूर्ण क्षेत्र को पुनर्जीवन

- भारत का विनिर्माण क्षेत्र अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह अर्ध-कुशल और अकुशल - श्रमिकों के लिए रोजगार का एक प्रमुख स्रोत भी है।
- ऐसे में सरकार ने फर्स्ट टाइमर यानी पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों पर विशेष ध्यान देने के साथ विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना शुरू की है। यह पहल इन श्रमिकों के रोजगार को प्रोत्साहन प्रदान करती है।
- इससे राज़गार के शुरुआती चार वर्षों के दौरान उनके EPFO अंशदान के संबंध में कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को प्रत्यक्ष लाभ मिलता है।
- इस योजना से विनिर्माण क्षेत्र में कार्यबल में प्रवेश करने वाले लगभग 30 लाख युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है, साथ ही साथ उनके नियोक्ताओं को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

योजना का उद्देश्य:

- यह एक रणनीतिक कदम है, जो कई उद्देश्यों को पूरा करता है। सबसे पहले, यह निर्माताओं को अधिक श्रमिकों को काम पर रखने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी को कम करने में मदद मिलती है।
- दूसरा, यह विनिर्माण क्षेत्र में एक कुशल कार्यबल के विकास का समर्थन करता है, जो उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए आवश्यक है।
- तीसरा यह भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स कपड़ा और मोटर वाहन जैसे प्रमुख उद्योगों में सरकार के व्यापक प्रयास के साथ तालमेल कायम करता है।

महत्व:

- विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देकर, सरकार न केवल रोजगार पैदा कर रही है, बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए आधार भी तैयार कर रही है। एक जीवंत विनिर्माण क्षेत्र निर्यात को बढ़ावा दे सकता है, विदेशी निवेश को आकर्षित कर सकता है और आपूर्ति श्रृंखला में आर्थिक लाभों का एक लहर जैसा प्रभाव पैदा कर सकता है।

- इसके अलावा, EPFO के योगदान को प्रोत्साहनों से जोड़कर, यह योजना श्रमिकों के लिए अधिक 'सामाजिक सुरक्षा' कवरेज को भी बढ़ावा देती है, जो अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

नियोक्ताओं के लिए समर्थनः विस्तार संबंधी सुगमता

- व्यवसायों, विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई) को बढ़ने और विस्तार करने के लिए अनिवार्य समर्थन मिलना किसी भी अर्थव्यवस्था के फलने-फूलने के लिए आवश्यक है। छोटे और मध्यम उद्यम भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ होने के साथ-साथ रोजगार और आर्थिक गतिविधि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
- किंतु, जब इनके विस्तार की बात आती है, तो उन्हें अक्सर वित्तीय बाधाओं, अनावश्यक नियमों के बोझ और कुशल श्रम तक पहुंच की कमी सहित महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- नियोक्ताओं का समर्थन करने के उद्देश्य से, इन चुनौतियों का समाधान करने की दिशा में एक योजना तैयार की गई है।
- इस योजना के तहत, अपने कार्यबल का विस्तार करने वाले व्यवसायों को लक्षित करते हुए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके तहत, सरकार नियोक्ताओं को

1 लाख रुपये प्रति माह तक के वेतन पर नियुक्त किए गए प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए उनके EPFO अंशदान के लिए दो साल तक प्रतिमाह 3,000 रुपये तक की प्रतिपूर्ति करेगी। इस पहल से देश भर में 50 लाख लोगों को अतिरिक्त रोजगार मिलने की उम्मीद है।

महत्व:

- यह योजना नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों के लिए लाभदायक है। नियोक्ताओं के लिए, यह नए कर्मचारियों को काम पर रखने की लागत को कम करता है। इससे उनके लिए अपने संचालन का विस्तार करना और उत्पादन बढ़ाना आसान हो जाता है। कर्मचारियों के लिए, यह अधिक रोजगार के अवसर पैदा करता है और औपचारिक रोजगार तक उनकी पहुंच को बढ़ाता है। इतना ही नहीं, रोज़गार की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और करियर विकास जैसे सभी संबंधित लाभ भी देता है।

श्रम के लिए सेवाएं:

- बजट में ई-श्रम पोर्टल को अन्य मौजूदा प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ते हुए श्रम के लिए सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को एकीकृत करके असंगठित श्रमिकों के लिए 'वन-स्टॉप-सॉल्यूशन' के रूप में परिकल्पित किया गया है।

- यह विभिन्न सरकारी योजनाओं तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के अलावा रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और करियर संबंधी मार्गदर्शन की तलाश करने वाले श्रमिकों के लिए एक ही स्थान पर समाधान सुनिश्चित करता है।
- दो प्रमुख प्लेटफॉर्म श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल, उद्योग और व्यापार के लिए अनुपालन को आसान बनाने में सहायक रहे हैं। इनका नवीनीकरण किया जाएगा। इन पोर्टलों ने विशेष रूप से अक्सर जटिल विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों की कमी वाले छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए, श्रम कानून संबंधी अनुपालन को सरल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- पुनर्निर्मित पोर्टल बेहतर सुविधा और कार्यक्षमताएं प्रदान करेंगे। इससे व्यवसायों के लिए श्रम विनियमों का अनुपालन करना और भी आसान हो जाएगा।
- यह पहल भारत में व्यवसाय के अनुकूल माहौल बनाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। व्यवसायों के लिए संचालन को आसान बनाकर, सरकार निवेश, नवाचार और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित कर रही है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

विनिर्माण और रोजगार सृजन: उद्योग का परिदृश्य

परिचय:

- केंद्रीय बजट 2024-25 रोजगार और कौशल पर ध्यान केंद्रित करने के मामले में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार के साथ विकास के समावेशी एजेंडे के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है। रोजगार भारत में नीति निर्माताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।

- आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ते कार्यबल की जरूरतों को पूरा करने के लिए गैर-कृषि क्षेत्र में हर वर्ष लगभग 78.51 लाख नौकरियों का सृजन करने की जरूरत है। इस बजट में इस बड़ी चुनौती का समाधान करने का प्रयास किया गया है।

1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना:

- भारत, सबसे युवा आबादी और 28 वर्ष की औसत आयु के साथ, उद्योग की जरूरतों से मेल खाने वाले रोजगार योग्य कौशल से लैस कार्यबल का पोषण करके अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन कर सकता है।

- सरकारी योगदान और उद्योग द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) पर खर्च के साथ, शीर्ष 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना एक नया विचार है।
- ये प्रशिक्षु उद्योग विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करेंगे और पेशेवर नेटवर्क बनाएंगे जो नौकरी और स्वरोजगार के अवसरों का सृजन कर सकते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये प्रशिक्षु अन्य संस्थाओं में शीर्ष 500 कंपनियों की विश्व स्तरीय संस्कृति और प्रणालियों को अपनाने में मदद करेंगे, जिससे उन्हें आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी।

इसकी आवश्यकता क्यों है?

- उल्लेखनीय है कि भारत की तेजी से बढ़ती आबादी का 65 प्रतिशत 35 वर्ष से कम आयु का है और उनमें से कई के पास आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक कौशल नहीं है।
- अनुमान बताते हैं कि लगभग 51.25 प्रतिशत युवा रोजगार योग्य माने जाते हैं। दूसरे शब्दों में, कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के तुरंत बाद लगभग दो में से एक युवा रोजगार योग्य नहीं होता है।

- यह पहल शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग के बीच संबंध को मजबूत करने में मदद करेगी। यह सुनिश्चित करेगी कि शैक्षणिक कार्यक्रम उद्योग की जरूरतों के साथ बेहतर ढंग से तैयार किया जाए।

कामकाजी महिलाओं की 'कार्य-जीवन संतुलन' को संबोधित करना:

- सरकार द्वारा एक और समावेशी पहल उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और क्रेच की स्थापना की करना और कार्यबल में उनकी भागीदारी को बढ़ाना है।
- इस पहल का उद्देश्य महिलाओं के सामने आने वाली कार्य-जीवन संतुलन चुनौतियों का समाधान करके महिला कर्मचारियों की नौकरी छोड़ने की दर को कम करना है, जिससे उद्योगों के लिए उपलब्ध प्रतिभा पूल का विस्तार हो सके।

श्रम के उत्पादकता वाले पहलू पर भी ध्यान देने की आवश्यकता:

- श्रम से संबंधित एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू उत्पादकता है। इस बजट में, अगली पीढ़ी के सुधारों के लिए एक आर्थिक नीति ढांचा तैयार करने की घोषणा भी की गई है जिसमें उत्पादन के कारकों, अर्थात् भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमशीलता और प्रौद्योगिकी की उत्पादकता में सुधार शामिल होंगे।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- पिछले दो दशकों में दुनिया के जीवन स्तर में तेजी से वृद्धि हुई है, ऐसा उत्पादकता में मजबूत वृद्धि के कारण संभव हुआ है। हालांकि, ऐसे संकेत हैं कि दुनिया के कई हिस्सों में उत्पादकता वृद्धि फीकी पड़ रही है।
- भारत को यदि अपनी आर्थिक वृद्धि दर को एक चौथाई सदी तक बनाए रखना है और इसे टिकाऊ तरीके से करना है, तो यह महत्वपूर्ण है कि श्रम सहित उत्पादन के कारकों के लिए ये सुधार, उनकी उत्पादकता को बेहतर बनाने और बाजारों को कुशल बनाने के लिए अभी किए जाएं।

बजट में विनिर्माण; सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम और रोजगार पर ध्यान:

- बजट में विनिर्माण; सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम-एमएसएमई और रोजगार पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो हमारी विकास यात्रा में निर्णायक कारक साबित होगा।
- बजट में रोजगार के लिए प्रोत्साहन प्रदान करके, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के लिए समर्थन को मजबूत करके और इस क्षेत्र की लागत को कम करने वाले क्षेत्रों को संबोधित करके विनिर्माण क्षेत्र को बहुत व्यापक तरीके से संबोधित किया गया है।

- उल्लेखनीय है कि उच्च मूल्य-वर्धित विनिर्माण गतिविधियों की दिशा में संरचनात्मक परिवर्तन को पारंपरिक रूप से मुख्य मार्ग माना जाता है, जिसे अर्थव्यवस्थाएं उच्च आय स्तर प्राप्त करने और अपनी आबादी के लिए स्थायी आजीविका प्रदान करने के लिए अपना सकती हैं।

रोजगार के भविष्यगत चुनौती पर ध्यान देने की आवश्यकता:

- काम के भविष्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि यह एक ऐसा विषय जो तेजी से हो रही तकनीकी प्रगति, जनसांख्यिकी में बदलाव और बदलते आर्थिक परिदृश्य के संदर्भ में तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इसका भविष्य में हमारे रोजगार परिदृश्य पर प्रभाव पड़ेगा। काम का भविष्य स्वचालन, AI और गिग अर्थव्यवस्था के उदय की विशेषता है।
- ये परिवर्तन जहां नए अवसर लाते हैं, वहीं वे चुनौतियां भी पेश करते हैं जिनका हमें सक्रिय रूप से समाधान करना चाहिए।
- वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, 2023 के अनुसार, अगले पांच वर्षों में, वैश्विक स्तर पर 23 प्रतिशत नौकरियों में बदलाव की उम्मीद है। इस बदलाव में नौकरियों में 10.2 प्रतिशत की वृद्धि और 12.3 प्रतिशत की

गिरावट शामिल होने की संभावना है। नियोक्ताओं को उम्मीद है कि 69 मिलियन नई नौकरियों का सृजन होगा और 83 मिलियन नौकरियां खत्म होंगी जिससे 14 मिलियन नौकरियों या वर्तमान रोज़गार में 2 प्रतिशत की कमी हो जाएगी।

- इसलिए हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हमारे युवा और मौजूदा कार्यबल भविष्य के लिए तैयार हों।

निष्कर्ष:

- निष्कर्ष के तौर पर, केंद्रीय बजट 2024-25 में श्रम संबंधी घोषणाएं भारत के श्रम बाजार को मजबूत करने के लिए एक व्यापक रणनीति को दर्शाती हैं।
- भारत सरकार, रोजगार सृजन को प्राथमिकता देकर, महिलाओं की कार्यबल भागीदारी को बढ़ाकर, कौशल विकास को आगे बढ़ाकर, श्रम बाजार की दक्षता में सुधार करके और विनिर्माण और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर ध्यान केंद्रित करके, विकसित भारत के लिए समावेशी और सतत आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।